## एनएच घोषित सड़कों के टेंडर तक मेंटेनेंस करेगी राज्य सरकार

# बिहार की अच्छी सड़कें केंद्र के हवाले नहीं होंगी

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य सरकार अपनी अच्छी सड़कों को केन्द्र के हवाले नहीं करेगी। इसी के साथ केन्द्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीय उच्च पथ (एनएच) घोषित सड़कों का मेंटेनेंस राज्य सरकार तब तक करेगी जब तक केन्द्र इनके निर्माण के लिए टेंडर जारी नहीं कर दे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित बिहार पैकेज की सभी 54 योजनाओं का टेंडर अगले वर्ष मार्च तक हर हाल में कर दिया जाएगा।

पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने गुरुवार को उक्त घोषणा की। वह पीएम पैकेज के लिए बुलाई गई समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने अब तक राज्य की 52 सड़कों को सैद्धांतिक रूप से एनएच घोषित किया है, लेकिन समीक्षा के बाद यह तय हुआ कि उनमें 11 बेहतर स्थिति में हैं। इन्हें एनएच को नहीं दिया जाएगा। जिन 41 सड़कों को एनएच को देने की सहमति बनी उनकी लंबाई लगभग ढाई हजार किमी है। हालांकि इस मुतल्लिक एक बार और समीक्षा होगी। संभव है एनएच बनने वाली सड़कों की संख्या कुछ और कम हो जाए।

मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए सवा लाख करोड़ का जो पैकेज घोषित किया था उनमें 54 हजार करोड़ सड़कों के लिए था। इस पैसे से बनने वाली सड़कों व पुलों को 54 भाग में बांटा गया है। 24 भाग का काम एनएचएआई कर रहा है, तो शेष 30 का रोड मंत्रालय। इसमें 19 पैकेज का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा 14 पैकेज के लिए एजेन्सी का चयन कर लिया गया है। शेष 21 पैकेज के काम का टेंडर मार्च 2018 तक कर लिया जाएगा। पीएम के एक पैकेज में 12 रोड ओवर ब्रिज भी हैं। इनमें दस अरओबी के लिए एजेन्सी का चयन हो गया है तथा दो का काम प्रगति पर है।

### घोषणा

- पीएम पैकेज की सभी योजनाओं का टेंडर अगले वर्ष मार्च तक
- मंत्री बोले, पैकेज की 19 योजनाओं का काम शुरू हो चुका है

### बैठक में ये भी थे मौजूद

समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी एके मिश्रा और रोड मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी राजेश कुमार भी उपस्थित थे।